

संपादकीय

मणिपुर में सरकार और प्रशासन हिंसा और अराजकता को रोकने में पूरी तरह नाकाम

मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं में छह लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल हो जाने से साफ है कि तमाम कवायदों के बावजूद सरकार वहां शांति स्थापित कर पाने में नाकाम है। वहां हिंसा शुरू हुए करीब चार महीने हो गए हैं और इस बीच पुलिस से लेकर सेना तक का सहारा लेकर टकराव में शामिल गुटों को काबू में करने की कोशिशें जारी हैं। मगर आज भी वहां जैसे हालात हैं, उसके मद्देनजर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गौरतलब है कि मणिपुर में गुरुवार को चुराचांदपुर-बिष्णुपुर सीमा पर दो गुटों की गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई। चुराचांदपुर कुकी-जोमी बहुल इलाका है और बिष्णुपुर में ज्यादातर आबादी मैतेई समुदाय की है। ताजा संघर्ष में मारे गए लोगों में वहां के एक लोकप्रिय गीतकार की भी जान चली गई। मंगलवार से अब तक गोलीबारी में कुल नौ लोग मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं के बाद एक रिवायत की तरह पुलिस की ओर से फिर यही कहा गया है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सवाल है कि इन्हें लंबे संघर्ष और इसमें शामिल समूहों के चिह्नित होने के बावजूद सरकार और प्रशासन हिंसा और अराजकता को रोकने के मामले में क्यों लाचार दिख रही है। विडंबना है कि इस मसले पर उच्चतम न्यायालय सरकार को हिदायत दे चुका है कि वह हिंसा पर लगाम लगाने और शांति कायम करने के लिए ठोस कदम उठाए, जरूरी कार्रवाई करे। उसकी तरफ से गठित निगरानी समिति मणिपुर में काम शुरू कर चुकी है। मगर इससे अफसोसनाक और क्या होगा कि इसके बावजूद वहां के कई इलाके अब भी अशांत हैं। हालांकि राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण में कर लेने का भरोसा जाता रही है, लेकिन पिछले कई महीने से जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि हिंसा को रोक पाने में वहां की पुलिस व्यापक पैमाने पर नाकाम साबित हुई है। यह बेवजह नहीं है कि जिन इलाकों में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव अधिक था और उससे निपटना एक जटिल चुनौती थी, वहां हालात पर काबू पाने के लिए सेना को भी उतारा गया। पर ऐसा लगता है कि इस समस्या से उपजी चिंता गहराती जा रही है। गौरतलब है कि बीती मई की शुरूआत में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के मसले पर शुरू हुए विरोध के बाद हिंसा भड़क गई और उसका दायरा फैलाता चला गया। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष में लगभग दो सौ लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शांति समिति का भी मन्त्र लिया गया था। मगर अब भी दोनों समुदायों के

रहे ये बनता नाम!



है रचना इतिहास ।
हो रहा हर काम ॥
है यह स्वर्णिम काल ।
रहे ये बनता नाम ॥
गढ़ना कीर्तिमान है ।
मिल रहा सहयोग ॥
दिल से है प्रयास ।
बन रहा भी योग ॥
तरह तरह के रोज ।
करना नया प्रयोग ॥
है छलांग लगानी ।
ऐसा ही उपयोग ॥
दुनिया है टिकाए ।
नजरें इस प्रकार ॥
है ऐसा प्रतीत ।

ललित गर्ग

नया भारत-सशक्त भारत बनाने की बात हो रही है, नई शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा, शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करते हुए उस पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन सब प्रयत्नों के बावजूद चिंता की बात यह है कि पूरे देश में खुदकुशी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। साल 2020 में 12500 से अधिक, तो 2021 में 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के हैं। कोटा में इसी रविवार को दो और छात्रों ने खुदकुशी कर ली। इसके साथ इस साल कोटा में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 23 हो गई है, जो बहुत ही गंभीर मसला है। राजस्थान की इस शिक्षा नगरी में दो महीनों में 9 छात्रों ने सुसाइड कर चुके हैं। यहां लगातार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे सरकार, प्रशासन या कोचिंग इंस्टिट्यूट की लापरवाही है या कुछ और? सुसाइड हब बन रहे कोटा के इस स्थान पक्ष को लेकर अब इस आपदा का हल तो ढूँढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि महामारी बनती इस समस्या के कारण हमें नहीं पता।

महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा जरुरी है, कहा भी जा रहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार भी है जिससे इंसान न केवल खुद को, बल्कि समाज, राष्ट्र एवं दुनिया को भी बदल सकता है। फिर शिक्षा के आसापास ऐसी कौन-सी विसंगतियाँ एवं विडम्बना है कि छात्रों में आनन्दहत्या की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। सब जानते हैं कि शिक्षा के व्यवसाय बनने से उसमें अनेक कुचेश्वर प्रवेश कर रही हैं, छात्रों से अच्छे परीक्षा परिणाम देने का दबाव बनाया जा रहा है अधिक प्रतिस्पर्धा एवं होड ने छात्रों पर प्रेशर बनाया है, इसके साथ ही किस तरह से पैरंट्स अपने सपने बच्चों पर थोपते हैं। उन्हें आईआईटी, एनआईटीया भैंडिकल में ही बच्चों का सुनहरा भविष्य दिखता है, जिसे साकार करने के लिए कई अभिभावक कर्ज भी लेते हैं। मां-बाप के सपनों से दबा स्टडेंट्स जब कोचिंग संस्थानों में पहुंचता है तो तेज उस पर तैयारी और टेस्ट का प्रेशर डाला जाता है और यह कह कर र्थंडराया जाता है कि जेइ या एनडीटी दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाएँ हैं किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था कर्ता कामयाबी इसमें है कि शुरूआती से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा हासिल करने के मामले में गलताकार परिस्थिरां पार्ट जटिलता की बजाए

सहजता हो। अगर किसी वजह से पढ़ाई करने या उसमें सफलता हासिल करने में किसी विद्यार्थी के सामने अड़चनें आ रही हों तो उसे दूर करने के उपाय किये जाएं। लेकिन बीते कई दशकों से यह सवाल लगातार बना हुआ है कि एक बड़ी तादाद में विद्यार्थी स्कूल-कालेजों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने

के आखिरकार यहां सुसाइड के प्रमाणों में लगातार इजाफा क्यों हो रहे हैं। छात्रों के द्वारा अगर लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं तो सासाइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्यों नहीं कराइ जा रही है। इस संबंध कोविंग संस्थान और प्रशासन की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? जहन में एक ही सवाल बार-बार

**भविष्य के युद्धों की दशा-दिशा बदलने जा रहा है अमेरिका
रोबोट लड़ाके छुड़ाएंगे रसिया-चाइना जैसे दुश्मनों के छक्के**

नीरज कुमार दुबे

बदलते वैश्विक परिदृश्य में तकनीक
की वजह से बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन
बदलावों के चलते ही माना जा रहा है कि
भविष्य में होने वाले युद्ध पारम्परिक युद्धों
की तरह मैदान में नहीं लड़े जाएंगे। इस
संभावना को देखते हुए विभिन्न देश
अपनी-अपनी रक्षा तैयारियों में आज और
आने वाले भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से
बदलाव कर रहे हैं। साथ ही अब विश्व
स्तर पर यह भी सोचा जा रहा है कि बड़ी
सेना रखने की बजाय उसे छोटा और
आधुनिक रखने पर जोर दिया जाये। इसके
लिए अमेरिका ने जो कदम उठाया है उम्मीद
है कि अन्य देश भी उस राह पर आगे बढ़
सकते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका
की उप रक्षा मंत्री कैथलीन हिक्स ने एक
अहम घोषणा के तहत कहा है कि उनके
देश की सेना चीन की बढ़ती ताकत को
देखते हुए अगले दो वर्षों में हजारों स्वायत्त
हथियार प्रणालियों का उपयोग शुरू करने
की योजना बना रही है। देखा जाये तो
पिछले करीब एक दशक के आसपास
विभिन्न स्तरों में स्वतंत्र संचालन के लिए
मध्यम सैन्य प्रणालियाँ देजी से मापान्त दर्द

लगातार तेज होती चुनौती है। अमेरिका की प्राथमिकता है कि खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं को बनाया जाये। हम आपको बता दें न की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में लोग, अधिक टैक, अधिक जहाज अधिक मिसाइलें इत्यादि हैं। दूसरी अमेरिका के पास भले ही चीन से बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण हो सकते हैं, लेकिन चीन सैनिकों और रक्षा उपकरणों की संख्या के मामले में बाजी मार ले जाता है। इसलिए रेप्लिकेटर प्रोग्राम अब हजारों एट्रिबल ऑटोनॉमस सिस्टम का त्वरित निर्माण कर, अमेरिका को भविष्य के संभावित युद्ध जीतने में मदद करेगा। इसके अलावा, अमेरिका का मानना है कि चीन का ताइवान को लेकर जो रुख है उससे तनाव निर्ष में तब्दील होने की आशंका है। रोबोट किसी भी बड़े चीनी आक्रमण दम करने में अमेरिका के लिए कहीं हो सकते हैं। इसके अलावा और आगे की बात सोच रहा है। लल रेप्लिकेटर अभियान का लक्ष्य नवाद्धि के लिए रोबोट का बड़े पैमाने पादन कर एक नया रक्षा व्यवसाय करना भी है।

हाँ तक अमेरिका के इस नये और दम की बात है तो यह स्पष्ट है कि यदि अमेरिका इस राह पर आगे बढ़ता है तो वह बड़ी संख्या में स्वायत्त प्रणालियां तैनात करने वाला पहला देश हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अन्य देश उससे बहुत पीछे होंगे। माना जाता है कि चीन भी लड़ाई लड़ने वाले रोबोट बना रहा है। इसलिए चीन को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लड़ाकू ड्रोन उत्पादन में महारत है। हम आपको यह भी बता दें कि स्वायत्त सैन्य ड्रोन की अधिकतर तकनीक व्यापक रूप से उपलब्ध है। लीबिया और इजराइल तथा कुछ अन्य देशों द्वारा स्वायत्त हथियार प्रणालियां तैनात किए जाने की खबरें भी हाल में सापेन आई हैं। यही नहीं, तुर्की निर्मित ड्रोन युद्ध में महत्वपूर्ण सांकेत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी स्वायत्त हथियारों की संभावनाओं में गहरी दिलचस्पी रखता है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल आज एमक्यू-28 घोस्टबैट स्वायत्त फास्ट जेट एयर वाहन, रोबोट प्रणाली वाले बख्तारबंद वाहन, रोबोट लॉजिस्टिक ट्रक और रोबोट पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। वह तिमार सागर में समुद्री सीमा निगरानी के लिए ब्लूबॉटल रोबोट सेलबोट का उपयोग कर रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एस्स्वाइंपीएक्यू युक्रेन के लिए अपने कई सस्ते, कार्डबोर्ड से बने ड्रोन भेज रही है। बहरहाल, अमेरिकी उप रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि क्या एक नई बहादुर सेना का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस बारे में चर्चाओं के दौरान कुछ चिंताएं भी उभर कर आई हैं।

**चंद्रयान-3 की सफलता से पश्चिमी देशों का चिढ़ना
दशार्ता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है**

प्रह्लाद सबनानी

अंतरः भारत चल पड़ा है
विश्व गुरु बनने की राह पर। परंतु,
पश्चिमी देशों में कुछ विधानसंसदों
जीवों को शायद यह रास नहीं आ
रहा है क्योंकि भारत, ब्रिटेन का
कभी औपनिवेशिक देश रहा है
और इन देशों की नजर में यह कैसे
हो सकता है कि ब्रिटेन के चन्द्रमा
पर पहुँचने के पूर्व ही उनका एक
पूर्व औपनिवेशक देश अपना
चन्द्रयान-3 सफलता पूर्वक चन्द्रमा
पर उतार ले। भारत, पूरे विश्व में,
पहला देश है जिसने चन्द्रयान-3
को चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर
सफलतापूर्वक उतार लिया है।
अन्यथा, विश्व का कोई भी देश,
अमेरिका, रूस एवं चीन सहित,
अभी तक चन्द्रमा के दक्षिणी पोल
पर अपना यान उतारने में सफल
नहीं हो सका है। निश्चित ही भारत
की यह सफलता न केवल भारत
के लिए बल्कि विश्व के समस्त
देशों के लिए गर्व का विश्व होना
चाहिए। यदि चन्द्रयान-3 अपने
उद्देश्यों में सफल हो जाता है तो
यह विश्व की भी उपलब्धि होगी।
चन्द्रमा पर पानी उपलब्धि है अथवा
नहीं, चन्द्रमा पर किस प्रकार के
खनिज पदार्थ (सोना, ज्वेटिनम्

टाइटेनियम, यूरेनियम, आदि)
रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक तत्व
मिट्टी एवं अन्य तत्व पाए जाते हैं
आदि का पता लगने पर क्या इस
जानकारी का लाभ केवल भारत
को ही होने जा रहा है अथवा क्या
विश्व के अन्य देश भी इसके
जानकारी का लाभ उठा सकने की
स्थिति में नहीं होंगे? परंतु, पश्चिमी
देशों में कुछ तत्व भारत की इस
महान उपलब्धि को सकारात्मक
दृष्टि से न देखते हुए इस संदर्भ में
अपनी नकारात्मक सोच को आगे
बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और
समझव ह कि भारत के प्रति उनकी
यह नकारात्मक सोच इन देशों के
लिए भविष्य में हानिकारक सिद्ध
हो।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून
छापा है जिसमें बताया गया है कि
विशिष्ट वर्ग के दो नागरिक एक
कक्ष (कैबिन) में बैठे हैं एवं इनमें
से एक संभान्त व्यक्ति एक अखबार
में भारत के मंगल मिशन के सम्बन्ध
में जानकारी पढ़ रहा है। इस कक्ष
के बाहर भारतीय गरीब किसान के
रूप में एक गाय को लेकर एक
व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। जो दरवाजे पर दस्तक देता हुआ
दिखाई दे रहा है। इस कार्टून से

ऐसा महसूस कराए जाने का प्रयास किया जाना प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक गरीब भारत देश, पश्चिमी देशों से अपने मंगल मिशन के लिए सहायता मांग रहा हो। संभवतः भारत के चन्द्रयान-3 की सफलता को पश्चिमी देशों में कुछ तत्व पचा नहीं पा रहे हैं। एक ब्रिटिश पत्रकार पेट्रिक क्रिस्टी ने भारत को चन्द्रयान-3 को चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर सफलता पूर्वक उतारे जाने की बधाई देते हुए यह मांग की है कि ब्रिटेन द्वारा भारत को उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता राशि को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि उसके अनुसार चूंकि भारत की आधी आबादी गरीबी का जीवन जी रही है अतः ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जा रही आर्थिक सहायता राशि का उपयोग भारत में गरीबी मिटाने के उद्देश्य से न किया जाकर अंतरिक्ष में अपने चन्द्रयान भेजने के लिए किया जा रहा है। इस ब्रिटिश पत्रकार का दावा है कि ब्रिटेन द्वारा भारत को वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के बीच 230 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है। उक्त पत्रकार का यह भी कहना है कि यदि भारत अपने राकेट को अंतरिक्ष में भेज तो भारत को ब्रिटेन के पास लेकर मदद के लिए नहीं चाहिए। जबकि इस संदर्भ में ब्रिटेन के पास आर्थिक समांगने के लिए गया ही नहीं है संदर्भ में ब्रिटेन द्वारा सरकार पर उपलब्ध कराई गई जानक अनुसार ब्रिटेन ने भारत को भी प्रकार की वित्तीय सुउपलब्ध नहीं कराई है परंतु ने वर्ष 2015 के बाद से भव्यवसाय को बढ़ावा देने के से निवेश जरूर किया है भारत के बाजार में ब्रिटेन योगदान बढ़ा सके एवं ब्रिटेन नागरिकों के लिए रोजगार अवसर निर्मित हो सकें।

यह भी एक वास्तविक कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन है और इस संदर्भ में हाल भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए अर्थव्यवस्था को आकार में से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। परंतु, कुछ ब्रिटिश राज एवं पत्रकार इस तथ्य को सही नहीं कर पा रहे हैं तो

अपनी साम्राज्यवादी सोच से भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे तत्व आज भी भारत को अपनी एक कालोनी (उपनिवेश) के रूप में ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भारत कैसे ब्रिटेन से पहले चन्द्रमा पर पहुंच सकता है। जबकि आज वस्तुरिक्ति यह है कि ब्रिटेन की आर्थिक हालत इतनी अधिक खराब हो गई है कि ब्रिटेन के नागरिकों को अपने बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों को अब यह समझना होगा कि यह 21वीं सदी है एवं वैश्विक पटल पर भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ चुका है। यह पश्चिमी देशों के हित में ही होगा कि वे भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनें एवं अपने आर्थिक हितों को भी बल प्रदान करें, इस बात को जितनी जल्दी समझें उनके लिए उतना ही अच्छा है क्योंकि अन्यथा वे स्वयं के आर्थिक हितों को नुकसान ही पहुंचा रहे होंगे। क्या ब्रिटेन इस बात को भल गया है कि औपनिवेशक खंडकाल में उसने भारत पर शासन के दौरान वर्ष 1765 से लेकर वर्ष 1938 तक भारत से 45 लाख करोड़ पाँड़ की लूट की है (यह तथ्य एक अध्ययन प्रतिवेदन में सामने आया है), हो सकता है यह राशि और भी अधिक रही हो। परंतु, उक्त राशि भी ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का 15 गुणा है। उक्त राशि को ब्रिटेन द्वारा भारत को लौटाए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ब्रिटेन द्वारा भारत में की गई भारी लूट के बावजूद भारत एक बार पुनः अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है एवं भारत को अपने मिशन चन्द्रमा ग्रह, मिशन मंगल ग्रह एवं मिशन सर्य ग्रह पर पश्चिमी देशों के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। भारत को वैसे भी अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित नयी सफलता की कहानियां गढ़ने की आदत पड़ चुकी है, और फिर चन्द्रमा के दक्षिणी पोल पर चन्द्रयान-3 को सफलता पूर्वक उतारना तो एक शुरूआत भर है। भारत का मिशन चन्द्रयान-3 तुलनात्मक रूप से बहुत किफायती रहा है। इस पूरे मिशन पर केवल लगभग 615 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि अन्य देशों यथा अमेरिका, रूस एवं चीन की इस तरह के मिशनों पर हजारों करोड़ रुपए की लागत आती रही है।

छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति चिन्ताजनक, सरकार को इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना होगा

के रहे ऐसे तो नहीं नहीं आखिर क से है? -बार जैसा कठोर, त्रासद एवं खौफनाक कदम उठा लेते हैं। पुणे स्थित कंसलटेंसी फर्म इनफिनियम ग्लोबल रिसर्च का अनुमान है कि इस साल के आखिर तक कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगा। यानी कोचिंग संस्थान समृद्ध एवं शक्तिशाली है कि वे चाहें तो बच्चों की मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए पहल कर सकते हैं। वे ऐसे छात्रों की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जिनका टेस्ट स्कोर कम हो और जो अक्सर क्लास से गायब रहते हों। ऐसा भी नहीं है कि कोटा के कोचिंग संस्थानों की ओर से इस तरह की पहल नहीं हुई है, लेकिन स्पष्ट है कि ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। विडम्बना तो यह है कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं केवल कोचिंग संस्थानों में ही नहीं हो रही है बल्कि आइआईटी, एनआईटी और आइआईएसईआर, आइआईएम व केन्द्रीय विश्वविद्यालय और इनके जैसे स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र भी आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न है कि उच्च नागरिक बनाने की बजाय ये संस्थान छात्रों को आत्महत्या बना रहे हैं तो उनके ऊपर एक काला बदनुमा दाग होने के साथ बड़ा सवाल भी खड़ा है कि ऐसे संस्थानों में क्या पढाई का स्तर तभी तभी नहीं है?

सरकार और देश के शिक्षाविदों को इस तथ्य को लेकर भी चिंता करनी ही होगी कि बीते पांच साल में इन उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले 92 विद्यार्थियों ने पढाई के बीच में ही आत्महत्या क्यों कर ली? ऐसे ही आईआईटी बुम्बई के फर्स्ट ईयर के छात्र दर्शन सोलंकी ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली। इसके बाद वहाँ के छात्रों से अधिकारिक तौर पर कहा गया है कि छात्र एक दूसरे से जी (एडवांस) रैक या गेट स्कोर के बारे में पूछताछ न करें। न ही ऐसा कोई सवाल करें जिससे छात्र की जाति, अमेरी-ग्रीष्मी और उससे जुड़े पहलू उजागर होते हो। इस तरह की गाइडलाइन की जरूरत केवल आईआईटी बुम्बई को ही नहीं, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एवं कोटा के कोचिंग संस्थानों को भी है। हालांकि बच्चों को मरोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकालने के लिए कोटा प्रशासन ने तकरीबन साल भर पहले एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसे एक भी कोचिंग संस्थान ने पूरी तरह फॉलो नहीं किया है, प्रश्न है कि प्रशासन ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाये? सवाल तो यह भी है कि क्या ऐसे सार्केतिक कदमों से आत्महत्या की बढ़ती संख्या जैसी गंभीर समस्याओं को हल किया जा सकता है।

